I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

*Research Article*

# आई टू यू टू (I2U2) और पश्चिम एशिया की उभरती भू-राजनीतिक व्यवस्था: भारत – इज़राइल रणनीतिक साझेदारी के अवसर एवं चुनौतियाँ

**भागीरथ रेगर**
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

**Corresponding Author:** * भागीरथ रेगर

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21720139

## सारांश

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में पश्चिम एशिया की भू-राजनीति तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। परंपरागत अरब–इज़राइल संघर्ष, ऊर्जा राजनीति और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से परिभाषित इस क्षेत्र में अब आर्थिक संपर्क, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार और लघुपक्षीय सहयोग भी क्षेत्रीय व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण निर्धारक बन रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग मंच I2U2 का उदय हुआ। यह शोध-पत्र I2U2 के उद्भव, उद्देश्यों तथा भू-राजनीतिक और भू-अर्थशास्त्रीय महत्त्व का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी की भूमिका का अध्ययन करता है। शोध का केंद्रीय तर्क है कि I2U2 भारत की बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता आधारित विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। साथ ही इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष, क्षेत्रीय अस्थिरता, ईरान से भारत के संबंध, सदस्य देशों की भिन्न प्राथमिकताएँ तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ इसकी संभावनाओं को प्रभावित करती हैं।

**Manuscript Information**

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-06-2026
- **Accepted:** 28-07-2026
- **Published:** 31-07-2026
- **IJCRM:**5(4); 2026: 540-542
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

**How to Cite this Article**

रेगर भा. आई टू यू टू (**I2U2**) और पश्चिम एशिया की उभरती भू-राजनीतिक व्यवस्था: भारत – इज़राइल रणनीतिक साझेदारी के अवसर एवं चुनौतियाँ. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4): 540-542.

**Access this Article Online**

www.multiarticlesjournal.com

**मूल शब्द:** I2U2, भारत–इज़राइल संबंध, पश्चिम एशिया, भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र, रणनीतिक साझेदारी, लघुपक्षवाद, बहु-संरेखण, रणनीतिक स्वायत्तता, खाद्य सुरक्षा।


© 2026 भागीरथ रेगर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## 1. प्रस्तावना

पश्चिम एशिया विश्व राजनीति के सर्वाधिक रणनीतिक क्षेत्रों में से एक रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, विशाल ऊर्जा संसाधन, महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग, अरब–इज़राइल विवाद, फिलिस्तीन प्रश्न तथा बाहरी महाशक्तियों की उपस्थिति ने इसे वैश्विक शक्ति-राजनीति का केंद्र बनाए रखा है। किंतु इक्कीसवीं सदी में इस क्षेत्र की राजनीति केवल तेल और सैन्य सुरक्षा के आधार पर नहीं समझी जा सकती। डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल संकट, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापारिक गलियारे और उन्नत प्रौद्योगिकी भी रणनीतिक शक्ति के प्रमुख साधन बन गए हैं। भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी तथा जनवरी 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार में सहयोग का विस्तार हुआ। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा ने संबंधों को नया राजनीतिक आयाम प्रदान किया। भारत ने इज़राइल के साथ निकटता बढ़ाते हुए अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ भी स्वतंत्र संबंध बनाए रखे। इसी क्रम में UAE के साथ भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई तथा 2020 के Abraham Accords ने इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच सामान्यीकरण की नई संभावनाएँ उत्पन्न कीं। अक्टूबर 2021 की चार देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता और 14 जुलाई 2022 के प्रथम I2U2 नेताओं के शिखर सम्मेलन ने इस सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान किया।

## 2. शोध समस्या

I2U2 के उदय ने पश्चिम एशिया में ऐसी लघुपक्षीय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें सैन्य सुरक्षा की अपेक्षा निवेश, तकनीक, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और संपर्क पर बल है। प्रमुख शोध समस्या यह है कि क्या I2U2 दीर्घकालीन क्षेत्रीय भू-अर्थशास्त्रीय व्यवस्था का आधार बन सकता है अथवा सदस्य देशों के तात्कालिक हितों पर आधारित सीमित सहयोगी मंच रहेगा। भारत के लिए यह प्रश्न रणनीतिक स्वायत्तता के कारण और जटिल है, क्योंकि वह इज़राइल और अमेरिका के साथ सहयोग के साथ-साथ अरब देशों, फिलिस्तीन और ईरान के साथ भी महत्त्वपूर्ण संबंध बनाए रखता है।

## 3. शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य I2U2 के उद्भव की राजनीतिक एवं रणनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना; पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति में इसके महत्त्व का विश्लेषण करना; भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को समझना; भारत के लिए आर्थिक, तकनीकी, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी अवसरों का मूल्यांकन करना; प्रमुख क्षेत्रीय एवं संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण करना; तथा I2U2 को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण की नीति के संदर्भ में समझना है।

## 4. शोध प्रश्न एवं परिकल्पना

अध्ययन यह परीक्षण करता है कि I2U2 के गठन के पीछे प्रमुख भू-राजनीतिक एवं भू-अर्थशास्त्रीय कारक क्या हैं; क्या यह पश्चिम एशिया में लघुपक्षवाद का नया मॉडल है; भारत–इज़राइल संबंध इसकी कार्यक्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं; तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए इसका क्या महत्त्व है। केंद्रीय परिकल्पना है कि I2U2 पारंपरिक सुरक्षा-केंद्रित गठबंधन व्यवस्था की अपेक्षा विकास, प्रौद्योगिकी, निवेश और संपर्क आधारित लघुपक्षीय सहयोग के उभरते मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है तथा भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी इसके प्रमुख प्रेरक तत्वों में से एक है।

## 5. शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों, I2U2 संयुक्त वक्तव्यों, सरकारी रिपोर्टों, पुस्तकों, शोध-पत्रों और प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की सामग्री जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण के लिए यथार्थवाद, उदार संस्थागतवाद, भू-अर्थशास्त्र तथा लघुपक्षवाद की अवधारणाओं को आधार बनाया गया है।

## 6. पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति

पश्चिम एशिया में अब पारंपरिक सुरक्षा राजनीति के साथ बहुध्रुवीयता, आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण हो चुकी है। चीन की आर्थिक उपस्थिति, रूस की क्षेत्रीय भूमिका, खाड़ी देशों की आर्थिक विविधीकरण रणनीतियाँ तथा इज़राइल–अरब सामान्यीकरण ने क्षेत्रीय संरचना में बदलाव किया है। 2020 के Abraham Accords ने UAE और इज़राइल के बीच औपचारिक संबंधों को गति दी और ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं की संभावना बढ़ाई जिनमें इज़राइली तकनीक, खाड़ी की पूंजी और भारतीय उत्पादन क्षमता व बाजार का संयोजन संभव हो।

## 7. I2U2 का स्वरूप और पूरक क्षमताएँ

I2U2 के सहयोग क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रमुख हैं। इसकी संरचना functional minilateralism का उदाहरण है। भारत विशाल बाजार, मानव संसाधन, IT और कृषि क्षमता प्रदान करता है; इज़राइल कृषि-तकनीक, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवाचार में विशेषज्ञता रखता है; UAE पूंजी, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स क्षमता प्रदान करता है; जबकि अमेरिका वैश्विक पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी और रणनीतिक समर्थन उपलब्ध कराता है। इन पूरक क्षमताओं का संयोजन I2U2 की मूल शक्ति है।

## 8. भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी

भारत–इज़राइल सहयोग रक्षा और सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, विज्ञान एवं उन्नत प्रौद्योगिकी तक विस्तृत हुआ है। आतंकवाद-रोधी सहयोग, निगरानी एवं रक्षा प्रणालियों ने रणनीतिक विश्वास को बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती और Centres of Excellence का मॉडल उपयोगी रहा है। जल पुनर्चक्रण, desalination और drip irrigation में इज़राइली विशेषज्ञता भारत के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष महत्त्व रखती है। भविष्य में AI, cybersecurity, digital technologies, semiconductors और startups द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा कर सकते हैं।


© 2026 भागीरथ रेगर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

### 9. खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा

2022 के I2U2 नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में UAE द्वारा भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों के विकास के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना व्यक्त की गई थी। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक, जल संरक्षण, खाद्य अपव्यय में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था। ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात में लगभग 300 मेगावाट की पवन एवं सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की दिशा में कार्य का उल्लेख हुआ। ये पहल I2U2 के भू-अर्थशास्त्रीय चरित्र को स्पष्ट करती हैं।

### 10. भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व

I2U2 भारत की पश्चिम एशिया नीति को ऊर्जा आयात और प्रवासी हितों से आगे बढ़ाकर निवेश, तकनीक, संपर्क और रणनीतिक भागीदारी तक विस्तृत करता है। यह भारत को इज़राइल और प्रमुख अरब साझेदार UAE के साथ एक साझा विकासात्मक मंच देता है। तकनीकी सहयोग, निवेश, आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा भारत के प्रमुख हित हैं। यह व्यवस्था भारत की बहु-संरेखण नीति के अनुरूप है, जिसमें विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ मुद्दा-आधारित सहयोग करते हुए निर्णयात्मक स्वायत्तता बनाए रखी जाती है।

### 11. चीन, IMEC और क्षेत्रीय संपर्क

I2U2 के आधिकारिक उद्देश्यों में चीन-विरोध घोषित आधार नहीं है, फिर भी पश्चिम एशिया और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति इसके भू-राजनीतिक संदर्भ का हिस्सा है। भारत के लिए I2U2 को केवल चीन-प्रतिरोधी मंच के रूप में देखना उचित नहीं होगा। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) और I2U2 अलग पहल हैं, किंतु दोनों में भारत, खाड़ी क्षेत्र, इज़राइल और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने का भू-अर्थशास्त्रीय तर्क दिखाई देता है।

### 12. प्रमुख चुनौतियाँ

इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष और अक्टूबर 2023 के बाद की क्षेत्रीय अस्थिरता I2U2 के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौती है। भारत को इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ फिलिस्तीन के प्रति अपनी दीर्घकालीन नीति और अरब देशों से संबंधों में संतुलन बनाए रखना है। ईरान भी भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर चाबहार और मध्य एशियाई संपर्क के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त I2U2 की हल्की संस्थागत संरचना, सदस्य देशों की अलग प्राथमिकताएँ, अमेरिका की बदलती क्षेत्रीय नीति और परियोजना क्रियान्वयन की गति इसकी दीर्घकालीन प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

### 13. नीतिगत सुझाव

भारत को I2U2 के अंतर्गत जल-संकटग्रस्त राज्यों में जल प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, कृषि मूल्य-श्रृंखला, cold chain, processing और export infrastructure, startup networks, AI, semiconductor, cybersecurity, space technology तथा clean energy पर प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत को I2U2 को अन्य पश्चिम एशियाई साझेदारियों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय पूरक मंच के रूप में विकसित करना चाहिए। फिलिस्तीन और ईरान के साथ स्वतंत्र संवाद बनाए रखना रणनीतिक स्वायत्तता की दृष्टि से आवश्यक है।

### 14. निष्कर्ष

I2U2 पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। यह औपचारिक सैन्य गठबंधन की अपेक्षा समस्या-केंद्रित और विकासोन्मुख लघुपक्षीय सहयोग की दिशा को दर्शाता है। भारत के लिए इसका महत्त्व अमेरिका, इज़राइल और UAE के साथ खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं में निहित है। भारत–इज़राइल संबंध इसकी संरचना का महत्त्वपूर्ण आधार हैं, किंतु इसकी वास्तविक सफलता परियोजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय स्थिरता और सदस्य देशों की दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। भारत के लिए सर्वाधिक उपयोगी दृष्टिकोण I2U2 को विकासात्मक लघुपक्षवाद और बहु-संरेखण के साधन के रूप में विकसित करना है।

### संदर्भ सूची


1. Ministry of External Affairs, Government of India. Joint Statement of the Leaders of India, Israel, United Arab Emirates, and the United States (I2U2). New Delhi: Government of India; 2022 Jul 14.
2. Ministry of External Affairs, Government of India. First I2U2 Leaders' Virtual Summit. New Delhi: Government of India; 2022.
3. Ministry of External Affairs, Government of India. Annual Report 2022–23. New Delhi: Government of India; 2023.
4. Ministry of External Affairs, Government of India. India–Israel Bilateral Relations. New Delhi: Government of India; 2026.
5. Ministry of External Affairs, Government of India. India–Israel Joint Statement. New Delhi: Government of India; 2026 Feb 26.
6. Jaishankar S. The India Way: Strategies for an Uncertain World. New Delhi: HarperCollins India; 2020.
7. Tanchum M. The India–Middle East Food Corridor: How the UAE, Israel, and India Are Forging a New Inter-Regional Supply Chain. Washington (DC): Middle East Institute; 2022.
8. Ministry of External Affairs, Government of India. Annual Reports and Official Statements Concerning India's Engagement with West Asia, Israel, UAE and I2U2. New Delhi: Government of India. Available from: Ministry of External Affairs publications.



**Creative Commons (CC) License**

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.


**About the Corresponding Author**

**भागीरथ रेगर** राजनीति विज्ञान के शोधार्थी हैं तथा ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान से शोध कार्य कर रहे हैं। उनकी शैक्षणिक रुचियाँ भारतीय राजनीति, लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक नीति एवं समकालीन राजनीतिक विमर्श से संबंधित हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा शोध प्रकाशनों में सक्रिय सहभागिता रखते हैं।




© 2026 भागीरथ रेगर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/